

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-408/2015/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक-II, जयपुर

...प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती रेखा खण्डेलवाल पत्नी श्री श्रीराम खण्डेलवाल, 4-एस-12, जवाहर नगर, जयपुर
2. श्रीमती सुमन शाह पत्नी श्री कमल कुमार शाह, ए-13, शास्त्री नगर, जयपुर
3. श्रीमती सजना कानूनगो पत्नी श्री नितिन कानूनगो, प्लॉट नं. 47, आनन्द भवन, न्यू कॉलोनी, पांच बत्ती, एम.आई. रोड, जयपुर

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

श्री बलवन्त कुमावत

अभिभाषक

....प्रार्थी की ओर से

....अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.12.2017

निर्णय

1. यह निगरानी राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, जयपुर द्वितीय द्वारा विद्वान अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर (जिसे आगे 'कलक्टर मुद्रांक' कहा गया है) के आदेश दिनांक 09.07.2014 प्रकरण संख्या 211/2012 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर ने उप पंजीयक जयपुर द्वितीय, द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को खारिज किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा जयपुर नगर चौकड़ी हवाली शहर, बापू नगर, गणेश मार्ग व ज्योति मार्ग पर एक प्लॉट के बटवारे का दस्तावेज पंजीयन हेतु दिनांक 19.08.2010 को उप पंजीयक, द्वितीय जयपुर के समक्ष पेश करने पर उप पंजीयक ने उक्त दस्तावेज अधिकतम मुद्रांक कर 10,000/- रुपये पंजीयन कर अप्रार्थी पक्ष से वसूल कर मूल दस्तावेज संबंधित पक्षकार को लौटा दिया। ऑडिट दल के आक्षेप पर उप पंजीयक द्वितीय जयपुर ने उपरोक्त दस्तावेज दिनांक 19.08.2010 को कमी मालियत माना है। इस आधार पर संपत्ति के मालियत रुपये 1,39,40,066/- मानते हुए अप्रार्थी को कमी मुद्रांक राशि रुपये 6,87,000/- जमा कराने हेतु धारा 54 का नोटिस दिये जाने के उपरांत नियत समय में राशि जमा नहीं कराये जाने पर कमी राशि रुपये

2m

लगातार.....2

6,87,000/- वसूली हेतु उप-पंजीयक ने रेफरेंस पेश किया। रेफरेंस ऑडिट आक्षेप के इस बिंदु पर आधारित था कि राज. मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 42 के अनुसार पैतृक संपत्ति की बाजार मालियत पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर देय होना चाहिये तथा प्रकरण में राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14) एफडी/डिवी/98-52 के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 को प्रभावशील मानते हुये रेफरेंस खारिज किया है जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक उपस्थित आये।

4. विभागीय पैरोकार राज ने निवेदन किया कि ऑडिट दल ने जांच के दौरान इस दस्तावेज को कमी मालियत का माना है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 के आर्टिकल-42 के अनुसार विभाजन पत्र के दस्तावेज में संपत्ति की मालियत पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है। प्रश्नगत दस्तावेज में कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है। प्रश्नगत दस्तावेज की कीमत रुपये 1,39,40,006/- होती है। इस आधार पर अंतर राशि रु. 6,87,000/- मय शास्ति वसूली के आदेश दिये जाने चाहिये। इन्होंने यह भी कथन किया कि प्रकरण में जिस संपत्ति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था वो सम्पत्ति पैतृक नहीं होकर श्रीमती यशोदा देवी पत्नि हरिनारायण की स्वयं अर्जित आय से क्रय की गई सम्पत्ति थी इस कारण वो पैतृक सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती है व जो विभाजन पत्र निष्पादित किया गया है उस पर उपरोक्त वर्णित अधिसूचना लागू नहीं होने से पूर्ण मुद्रांक कर अदा करने की जवाबदेही बनती है। उपरोक्त निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत, विधिविरुद्ध है जो निरस्त करने योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी मानी है जो विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विभागीय पैरोकार की बहस को सुना गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगा है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि मुद्रांक कर बाजार मूल्य के अनुसार देय है अथवा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 के अनुसार देय है।

9. प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना वर्तमान अधिनियम के असंगत है या नहीं तथा इसका लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 19.08.2010 पर देय है या नहीं। इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91 (2) का अवलोकन किया जाता है जो निम्न प्रकार है :-

91. Repeal and Savings — (2) Any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under the enactment hereby repealed shall be deemed to have been made or issued under the provisions of this Act, in so far as such appointment, notification, notice, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this Act and shall continue in force, unless and until it is superseded by an appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under this Act.

इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना नये अधिनियम में तब तक लागू होगी जब तक कि यह अधिसूचना अतिष्ठित (Superseded) न कर दी जावे। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 को प्रत्याहारित करने के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से कोई परिपत्र या अधिसूचना या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 (1) निम्न प्रकार है:-

9 - Power to reduce, remit or compound duties (1) The Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may by rule or order published in Official Gazette, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the territories under its administration, the duties with which any instruments or any particular class of instruments, or any of the instruments belonging to such class, or any instruments when executed by or in favour of any particular class of persons, or by or in favour of any member of such class are chargeable.

इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को जनहित में शुल्क को कम करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई है जिसमें भी राज्य सरकार को शुल्क कम करने की शक्तियाँ थी। इस प्रकार जिन शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत शुल्क में रियायत की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जारी की गई है, वही शक्तियाँ राज्य सरकार को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त है तथा यह अधिसूचना नये अधिनियम के अन्तर्गत असंगत नहीं मानी जा सकती।

इस संबंध में मुद्रांक विभाग द्वारा ली गई विधिक स्थिति हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर का परिपत्र संख्या 24/2015 क्रमांक : एफ 7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 अवलोकनीय है जो निम्नुसार है :- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से

पूर्व लागू राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दी गई मुद्रांक शुल्क की रियायतें वर्तमान में प्रभावी होने के संबंध में :- "राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.2(50)वित्त/कर/10 दिनांक 01.12.2010 द्वारा विधि विभाग की राय के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि राज. स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91(2) के अनुसार राजस्थान स्टाम्प लॉ (अडप्टेशन) एक्ट, 1952 (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899) के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचनायें नये अधिनियम में भी जारी की गई समझी जावेगी, जब तक की वे वर्तमान अधिनियम, 1998 के प्रावधानों से असंगत न हों। पूर्व अधिनियम में स्टाम्प शुल्क को कम करने की शक्तियां राज्य सरकार को थी तथा नये अधिनियम की धारा 7 में भी ये शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त हैं। राज्य सरकार के उपरोक्त मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि पूर्व अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क में रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं।"

विभाग स्वयं द्वारा ली गयी उपरोक्त विधिक धारणा से भी स्पष्ट है कि मुद्रांक शुल्क में रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 05.06.2012 पर देय है।

10. निगरानी का अन्य बिन्दु यह है कि जिस संपत्ति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था वह संपत्ति पैतृक नहीं होकर श्रीमति यशोदा देवी की स्वयं अर्जित आय से क्रय की गई संपत्ति थी जिससे पैतृक संपत्ति नहीं मानी जा सकती। अतः इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि विचाराधीन दस्तावेज से संबंधित संपत्ति पैतृक है या नहीं।

पैतृक संपत्ति के संबंध में The Advanced Law Lexicon (Law Dictionary compiled and edited by P. Ramanatha Aiyar Published by Wadhwa & Company Nagpur, India 3rd Edition Reprint 2007) में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :-

Ancestral Property : If property came to a son as gift from his father, it can not be regarded his ancestral property. **Ancestral properties in the ordinary sense mean property of the father which is inherited. Ancestral property does not necessarily mean property which has been a long time in a family, it rather means, property derived from the proprietor's father.** इस डिक्शनरी में पैतृक संपत्ति के संबंध में की गई व्याख्या से यह स्पष्ट है कि यदि कोई संपत्ति पिता या उच्चतर श्रेणी के पूर्वजों से कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वह पैतृक संपत्ति की श्रेणी में है। स्वाभाविक रूप से माता की सम्पत्ति विरासतन प्राप्त होने से वह सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में है।

2m

बटवारनामा दस्तावेज पंजीयन दिनांक 19.08.2010 में बटवारनामा अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित हुआ है। श्रीमति यशोदा देवी का स्वर्गवास 08.10.1998 में होना दस्तावेज में अंकित है तथा दस्तावेज में यह उल्लेख है कि दस्तावेज से संबंधित संपत्ति श्रीमति यशोदा देवी द्वारा क्रय की गई थी। इस प्रकार संपत्ति श्रीमति यशोदा देवी की स्व-अर्जित संपत्ति है जो कि उनके मृत्यु के पश्चात विरासतन प्राप्त हुई है जो अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति मानी जायेगी। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है कि बटवारनामा से संबंधित संपत्ति पैतृक नहीं है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर बटवारनामा से संबंधित संपत्ति अप्रार्थीगण को उनके मृत्यु के बाद संपत्ति विरासतन प्राप्त होने के कारण पैतृक एवं ऐसे दस्तावेज पर अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 लागू होने के कारण निगरानी सारहीन है एवं खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।

(^{नरेश्वर}
नरेश्वर)
सदस्य